

>

Title: Need to open sub-post offices in every village having population of 1000 or more in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर भारत सरकार के डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have already started with the 'Zero Hour'. Nothing except what Shri Ganesh Singh is saying will go on record.

*(Interruptions)**

श्री गणेश सिंह : डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि देश के कई ऐसे बड़े गांव हैं, जहां पोर्ट आफिस नहीं हैं, जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पोर्ट आफिसों के माध्यम से हितग्राहियों के खाते खोलने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेशन इत्यादि के भूगतान का काम कराने की नीतियां बनायी हुई हैं। ऐसे मंत्रालय ने ऐसा टिकट भी पोर्ट आफिस से देने की घोषणा की है। इसी तरह से मनरेगा में मजदूरों के भूगतान के खाते भी वर्धी खोले गए हैं। लेकिन आज यह भी देखा जा रहा है कि देश के कई सुदूर अंतर्गत में 15-15 किलोमीटर तक कोई पोर्ट आफिस नहीं है। मैं उठाफण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में कोटर एक ऐसी जगह है, जहां तहसील मुख्यालय है और आज तक वहां उप-डाकघर नहीं बना है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि देश में एक हजार की आबादी के उन सभी गांवों में उप-डाकघर खोले जाएं और केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं चलायी हैं, पोर्ट आफिस तक उन योजनाओं को लोगों तक ठीक ढंग से डम तोग चला सकें, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों में पोर्ट आफिस खोले जाएं।
